1	2	3	4	5	6
7.	Jammu and Kashmir	5,000	—	—	—
8.	Karnataka	2,94,244	1,50,036	1,08,107	25,510
9.	Kerala	1,28,202	83,259	56,109	99,159
10.	Madhya Pradesh	2,57,982	1,47,317	89,230	35,025
11.	Maharashtra	3,73,620	3,66,202	2,87,452	79,707
12.	Manipur	1,029	424	424	326
13.	Orissa	1,51,362	1,31,020	1,15,685	90,752
14.	Punjab	48,116	15,174	13,694	3,250
15.	Rajasthan	2,58,248	2,32,064	1,31,741	28,853
16.	Tamil Nadu	89,083	82,147	71,414	49,789
17.	Tripura	1,926	1,844	1,430	1,223
18.	Uttar Pradesh	2,93,901	2,68,625	2,40,259	2,00,293
19.	West Bengal	1,71,447	1,19,702	71,084	2,10,251
20.	Dadra and N. Haveli	8,958	6,776	3,751	1,686
21.	Delhi	722	374	374	—
22.	Pondicherry	2,560	1,161	942	1,060
	Total	42,49,834	29,37,914	20,71,865	15,43,174

Increasing Production of Barley

314. SHRI GHULAM MOHAMMAD KHAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether any study has been made about the scope for export of raw barley by NAFED or any other organisation ;

(b) whether High Yielding Varieties of barley strains have been evolved and the same transferred to the farmers ; and

(b) the steps for increasing the area and production of barley in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) Neither NAFED nor Government of India have made any study about the scope for export of raw barley.

(b) A few improved varieties of barley were released during 70's for cultivation. Recently one more variety BHS-46 has been recommended only for cultivation in lower and mid hills of Northern hills zone. However, some high yielding varieties of barley possessing desirable characteristics have been evolved and are at present under various stages of testing.

(c) The strategy is to increase the productivity through popularisation of improved varieties and adoption of package of practices.

Procurement Price of Agricultural Commodities

315. SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI UTTAM RATHOD :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the recommendations made in recent weeks in regard to the procurement prices of different agricultural commodities ; and

(b) the decisions taken by Government on the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) In recent weeks the Government did not receive any recommendations of Agricultural Prices Commission in regard to the procurement prices of agricultural commodities.

(b) Does not arise.

भारतीय खाद्य निगम को घाटा

316. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 1984 के दैनिक नवभारत टाइम्स में "छीजन का गेहूं कहां जाता है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रति 100 किलोग्राम गेहूं के क्रय और विक्रय के दौरान लेनदेन में भारतीय खाद्य निगम को लगभग साढ़े चार किलोग्राम गेहूं का घाटा होता है और इस वर्ष 1982-83 में 120 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो छीजन से होने वाली हानि के क्या कारण हैं; और इस हानि को कम करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां।

(ख) 1982-83 के दौरान 52.32 करोड़ रुपये के मूल्य के 2.96 लाख मीटरी टन गेहूं की मार्गस्थ और भण्डारण में हानि हुई थी। परिचालनों की कुल मात्रा (खरीद और बिक्री) के संदर्भ में हानि की प्रतिशतता केवल 1.63 थी।

(ग) परिचालनों के स्वरूप और भारी मात्रा, जिसमें प्रत्येक मास कई लाख मीटरी टन की भारी मात्रा का परिवहन और स्टाक की बहु-हैंडलिंग शामिल होती है, की दृष्टि में मार्गस्थ और भण्डारण में खाद्यान्नों के स्टाक की कुछ हानि होना एक सामान्य बात होती है। सूखने, चोरी अथवा उठाईगिरी के कारण भी कुछ हानि हो सकती है।

हानियों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें लदान और उतरान के स्थानों पर उचित तौल की व्यवस्था करना, खुले भण्डारण में कमी करना, डिपुओं पर सुरक्षा के प्रबन्धों को कड़ा करना, भण्डारण और हैंडलिंग प्रौद्योगिकी में सुधार करना, विशेष स्क्वायडों द्वारा डिपुओं पर स्टाक की प्रत्यक्ष जांच करना, प्राप्ति, निर्गम और इतिशेष स्टाक आदि के बारे में सूचना देने की प्रणाली में सुधार करना आदि शामिल हैं।

Parity in Raw Cotton Price and Finished Goods

318. SHRI UTTAM RATHOD : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have agreed in principle to bring parity in the raw cotton prices and its finished goods i.e. cloth ;